Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069, Impact Factor: 5.660, Volume 07, No. 01, January-March, 2021, pp. 87-92

डिजिटल इंडिया: संभावना और चुनौतियाँ

डॉ. राजेन्द्र कुमार राय*

प्रस्तावना

भारत की आज़ादी के बाद सभी सरकारों ने प्रयास किया कि सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं का लाभ आमजन को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिल सके। इस हेतु समय–समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया और विभिन्न विभागों ने नीतियों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई। क्रियान्वयन कितना सफ़ल रहा ये सब देश के आर्थिक विकास और लोगों के जीवनस्तर में आने वाला बदलाव में परिलक्षित होता रहा है लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के एक व्यक्तव्य ने हमे सोचने को मजबूर किया कि क्या असल में हम अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए एक रूपये में से सिर्फ 15 पैसे ही जरुरतमंद लोगो तक पहुँच पाते हैं बाकी या तो नीतियों के क्रियान्वयन में चला जाता है और कुछ भाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। नये–नये कानूनों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तो प्रयास होते रहे लेकिन प्रक्रिया में होने वाली हानि को कैसे रोका जाए इसके प्रयास आज़ादी के बाद के दशकों में नाकाफ़ी रहे। गौर से देखने पर हम पाएंगे कि क्रियान्वयन की खामियाँ भी अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार को निमंत्रण देती हैं आज भी इस ख़ामी पर नियंत्रण करने के लिए सरकारें आज भी प्रयास कर रही हैं। इसमें सबसे काबिल प्रयास तो सम्पूर्ण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना कर किया गया जिसमें नीति निर्माण से लेकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया की जानकारी सर्वसुलभ उपलब्ध करायी गई। आमजन को सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने से अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार तो जनता की जागरूकता से स्वत: ही रुक जायेंगें।

सम्बन्धित विभाग के बाहर योजना के मुख्य बिन्दुओं को चस्पा कर पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास तो पहले से ही किये जा रहें थे। इसके साथ साथ स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियों के माध्यम से भी सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाया जा सकता है। इन सब से अलग एक नया तन्त्र प्रभावी रूप से विकसित हो रहा है जिसे हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं जिसके माध्यम से किसी भी जानकारी को कुछ ही पलों में पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बड़े से बड़े समूह तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो एक बार फिर हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के प्रयासों को याद करना होगा क्योंकि देश में कंप्यूटर लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है और उन्हीं के कार्यकाल में देश ने सूचना क्रांति के युग में प्रवेश किया। पहले, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता थी लेकिन आज इंटरनेट, मोबाइल के रास्ते हमारे हाथों में पहुँच कर हमारे जीवन को आसान बना रहा है। इंटरनेट को सर्वसुलभ बनाने में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने भी अहम भूमिका निभायी क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज हम मोबाइल के माध्यम से कभी भी और कहीं भी इन्टरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4G तकनीक आने के बाद तो इंटरनेट की दरों में भी भारी बदलाव आया है जिसने एक अद्भुद क्रांति का आगाज़ कर दिया है।

* सहायक आचार्य, ई.ए.एफ.एम. राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभर लेक जयपुर, राजस्थान।

पहले, लोग लंबी–लंबी कतारो में लग कर सरकारी योजनाओ के लिए आवेदन करते थे वहीं आज घर बैठे या नजदीकी ई–मित्र के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने के बाद उससे सम्बंधित सभी प्रकार की सूचना SMS या इंटरनेट की सहायता से बिना किसी कागज़ी कार्यवाही के प्राप्त कर सकते हैं। अतरू हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया है। इन सब के बावजूद अल्प आय के कारण एक बड़ा वर्ग इंटरनेट की सुविधा से महरूम है। देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में आज भी इन्टरनेट सुविधा का विस्तार नहीं हो पाया है दूसरी ओर मोबाइल फोन और इंटरनेट की दरों में अचानक आयी गिरावट के कारण एक वर्ग ऐसा भी है जो जानकारी के आभाव में इसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग की ओर बढ़ रहा है। सरकार का भी प्रयास है कि इन्टरनेट जैसे प्रभावी माध्यम का उपयोग सरकार की कार्यप्रणाली में किया जाए जिससे सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की है जिसका आदर्श वाक्य 'Power to Empower' है। इस योजना से आमजन किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है इस हेतु एक वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसका यूआरएल https://www.digitalindia.gov.in/है। अतः 90 के दशक का 'सूचना क्रांति' का काल आज 'डिजिटल युग' के रूप से जाना जाता है। निम्न स्तम्भो के आधार पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है:-

ब्रॉडबैंड हाईवे

सडकों का ऐसा जाल जो एक स्थान को दुसरे स्थान से जोड़ता है हाईवे कहलाता है उसी प्रकार ब्रॉडबैंड हाईवे एक स्थान से दुसरे स्थान को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है लेकिन ये जुड़ाव इन्टरनेट की सुविधा का प्रसार करने के लिए होता है। ब्रॉडबैंड हाईवे के निर्माण में निम्न कदम उठाए जाते हैं:-

- ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सुविधाओं का विस्तार करना।
- शहरी क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सुविधाओं का विस्तार हेतु करना।
- पंचायत स्तर तक के विभागों को तेज गति की इन्टरनेट सेवा के साथ–साथ क्लाउड स्टोरेज से जोड़ना।

मोबाइल कनेक्टिविटी की सार्वभौमिक उपलब्धता

देश में प्रत्येक 100 में से लगभग 89 लोगों के पास मोबाइल यूजर्स हैं अर्थात 40 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में और 22 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में इन्टरनेट का उपयोग करते हैं। आज भी देश की आबादी का एक बड़ा भाग मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाओं से महरूम हैं। देश का टेलिकॉम विभाग द्वारा ऐसे गांवों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। इन गांवों के लोग भी मोबाइल का उपयोग कर सकें इस हेतु यहाँ नेटवर्क विकसित करने के प्रयास तेज गति से किये जा रहें हैं। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों में भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जानकारी के अभाव में सरकारी सेवाओं के उपयोग नही कर पा रहा है अतः 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के तहत लोगों को डिजिटल माध्यम से रूबरू कराते हुए डिजिटल साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जन–जन तक पहुँचे इन्टरनेट

देश मे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवाओं की डीलीवरी पॉइंट के रूप में कार्य करता हैं। आज देश में लगभग 2.5 लाख से अधिक CSC ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहीं हैं और अब सरकार का प्रयास है कि डाकघरों के को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाए जिससे सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सके अतः लगभग 1.5 लाख डाकघरों को मल्टी सर्विस सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ई–गवर्नेंस

विभिन्न प्रकार की कागज़ी प्रक्रिया के कारण सेवाओं की प्रक्रिया जटिल हो जाती है इसलिए अब सभी प्रकार सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके और सम्पूर्ण प्रक्रिया में तेजी आये। इसके अन्तर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्न कदम उठाए जा रहें:-

- सभी विभाग एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का तैयार करेंगें जो सरल और यूजर फ्रेंडली होगा।
- आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कम से कम सूचनाओं का ही संग्रहण किया जाए।
- आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ही आसनी से ट्रैक किया जा सके इसकी व्यवस्था भी की जाएगी।
- सरकार के द्वारा ऑनलाइन रिपॉजिटरी सेवा को प्राम्भ किया गया है।
- UIDAI के तहत आधार दस्तावेज तैयार करना।

सेवाओं को ऑनलाइन डिलीवरी

नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2006 से ही कुछ सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा था और समय–समय पर इसमें अन्य विभागों को भी शामिल किया गया। इसी क्रम में Transforming e-Governance for Transforming Governance के विचार को ध्यान में रखते हुए मार्च 2015 से सरकार ने ई–क्रांति प्रोग्राम प्रारम्भ किया जिसमे सभी सरकारी विभाग प्रयासरत हैं कि विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से आमजन तक समय पर पहुंचाया जाए साथ ही ध्यान रखा जाये कि सम्पूर्ण प्रक्रिया कम खर्चीली हो।

सूचना की सभी के लिए उपलब्धता

किसी भी विभाग से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था इसके बाद भी यह आवश्यक नहीं था कि सूचना समय पर मिल जाए। सूचना के अधिकार (RTI) कानून ने किसी भी नागरिक को ये अधिकार अवश्य दिया है कि किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है लेकिन इसकी प्रक्रिया में निश्चित समय लगता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सभी विभागों ने अपनी सूचनाओं को वेबसाइट और अन्य ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शित करने लगे हैं। जनता की सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात में कमी लाने के लिए आवश्यक है कि देश में ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और सेवाओं का निर्माण हो सके इसके लिए सरकार द्वारा निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाजा जा रहा है। इस समपर्ण प्रक्रिया का परिणाम होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।

आईटी में रोज़गार

भारत ने जब से आईटी सेक्टर की ओर कदम बढ़ाया है तब से इस सेक्टर ने न सिर्फ रोज़गार सृजन में अहम् भूमिका निभायी हैं अपितु देश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान की है। आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल लोगों ने विदेशी धरती पर हमारे देश की छवि में एक सकारात्मक बदलाव किया है। आज भी आईटी सेक्टर में रोज़गार की असीम सम्भावना है लेकिन युवाओं में योग्यता के अभाव के कारण हम इस क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विभिन्न स्किल्स प्रोग्राम के तहत शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग देकर हम आईटी सेक्टर के लिए तैयार कर रहें। आजकल BPO और कॉल सेंटर में बढ़ते चलन का लाभ उठा कर हम हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकते है। इसके लिए Department of Electronics and Information Technology (DeitY) नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है।

जल्द परिणाम देने वाले प्रोग्राम

- विभिन्न सरकारी विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का आदान–प्रदान हो सके इसके लिए MeitY के द्वारा मैसेजिंग सेवा की शुरुआत की गई है।
- राष्ट्रीय महत्त्व के पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, शिक्षक दिवस पर लोगों को मैसेज भेजने के लिए ग्रीटिंग सेवा प्रारम्भ की गई है।
- सरकारी विभागों में समय पर उपस्थिति निश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की गई है।
- शिक्षा की अहमियत देखते हुए देश की सभी यूनिवर्सिटी में यूपि उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सरकारी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डमपजल ने एक सुरक्षित और प्रभावी ईमेल माध्यम तैयार किया है जिससे सरकारी कार्यप्रणाली की गति बढ़ सके।
- Department of Telecommunication और Ministry of Urban Development विभागों के द्वारा सार्वजानिक स्थानों पर WiFi सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
- बच्चो के बस्ते का बोझ कम करने के लिए किताबों को E-Book के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।
- आपदा के समय और मौसम की जानकारी के लिए SMS के माध्यम से सुचना उपलब्ध करायी जा रही है।
- देश में MeitY और Department of Women and Child Development विभाग द्वारा खोये हुए बच्चो की सूचना हेतु एक प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है।

डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को सूचना तकनीक विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रियान्वित किया जाता है और पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व कुशल शासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए Digital Indiaa की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया गया है:-

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी
- वित्त मंत्री, आईटी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होंगे सदस्य
- प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय, योजना, टेलीकॉम और कार्मिक सचिव विशेष आमंत्रित
- सूचना सचिव कमेटी के संयोजक

डिजिटल इंडिया के उत्पाद

- MyGov: सरकार में नागरिकों की सक्रीय भागीदारी के लिए बनाया गया मंच है। इच्छुक नागरिक देश में सुशासन के लिए अपने विचार और सुझाव इस माध्यम से सरकार तक पहुँचा सकते हैं।
- UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance): सरकार द्वारा प्रदत सभी सेवाओं की जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग में संपर्क करना पड़ता था लेकिन अब लगभग 1987 प्रकार की सेवाओं की जानकारी ही नहीं अपितु आवेदन भी उमंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- **डिजिलॉकर:** ऑनलाइन संग्रहण के लिए डिजिलॉकर को प्रारम्भ किया है जहाँ डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस जैसे अनेक के साथ साथ सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आर.सी. आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध रहेंगी जिससे उन्हें हमेशा साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल:** राज्य और केंद्र की अलग अलग छात्रवृतियों के लिए एक पोर्टल तैयार की जाए जिससे आवेदन में एकरूपता आये तथा समय पर छात्रवृति ऑनलाइन ही जारी की जा सके।
- **ई–हॉस्पिटल / ओआरएस:** लोग डॉक्टर से ऑनलाइन माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकें इस हेतु इस सेवा की शुरुआत हुई है। अभी तक कुछ ही हॉस्पिटल को इस सेवा से जोड़ा गया है।
- **ई–साइन:** ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर लोगों को डिजिटल साइन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है।
- **BHIM:** National Payment Corporation of India (NPCI) ने ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए BHIM (Bharat Interface for money) की शुरुआत की है। यह Unified Payment Interface (UPI) के आधार पर कार्य करता है। इसके माध्यम से कैशलेस इकोनॉमी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से आमजन को निम्नानुसार लाभ पहुँच रहा हैं

- सरकारी सेवाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिलने से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और कार्यवाही त्वरित गति से हो रही है जिससे लगने वाले समय में कमी आ रही है।
- सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता से काग़जी प्रक्रिया में कमी आएगी जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की और कदम बढ़ाएंगे।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढती है और पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार के स्तर में स्वतरू ही कमी आएगी।
- MyGov एप्लीकेशन से नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव दे सकते हैं जिसके कारण नागरिक विभिन्न योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं और नागरिकों की भागीदारी किसी भी प्रशासन के लिए सफलता की कुंजी है।
- विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को भुगतान करने की सुविधा मिली है। एक खाते से दुसरे खाते में कभी भी ट्रान्सफर किया जा सकता है।
- बैंकिंग और भुगतान की प्रकिया में ऑनलाइन को बढ़ावा मिलने से सभी प्रकार के लेनदेन का लेखा रखना संभव हुआ है जिससे कर चोरी की संभावनाओं में कमी आयी है अतः इसके कारण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आयेंगे।
- बैंकिंग और भुगतान में ऑनलाइन तरीकों के अपनाने से हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर सकते हैं।
- ऑनलाइन भुगतान बढ़ने से कंपनियों के द्वारा लोगों को समय समय अनेक प्रकार के डिस्काउंट मिलने लगे हैं।
- ऑनलाइन सुविधा सेतेजी से कार्य होने लगे हैंऔर मैनपॉवर में कमी आयी है।

डिजिटल इंडिया अनेक विचारों और संकल्पनाओं के मिश्रण से बना एक ऐसा कार्यक्रम हैं जिसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और कुशल प्रशासन प्राप्त किया जा सकता है यदि इसके मार्ग में आने वाली निम्न चुनौतियों का सामना प्रभावपूर्ण तरीके से कर लिया जाए :-

- डिजिटल इंडिया एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो इन्टरनेट के माध्यम से क्रियान्वित होता है इसके लिए सभी स्थानों को तेज गति के इन्टरनेट से जोड़ना आवश्यक है।

- तकनीक में दिन प्रतिदिन नई नई खोजें हो रहीं हैं जिसके करना उपलब्ध साधन बहुत ही कम समय में चलन से बाहर हो जाते हैं और नए संसाधनों को अपनाने पर सरकार को अतिरिक्त खर्च करना होता है।
- डाटा के ऑनलाइन संग्रहण के लिए अनेक तकनीकों का विकास करना आवश्यक है जिससे सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके।
- अनेक प्रकार की सूचनाएं गोपनीय प्रकृति की होती है और ये सरकार का दायित्व कि लोगो से सम्बंधित सभी जानकारियों की गोपनीयता बरकार रखे।
- नया सेक्टर होने के कारण सरकार को इससे सम्बंधित नए कानूनों को तैयार करने की जरुरत है जिससे ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.digitalindia.gov.in/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India
3. https://www.mygov.in/group/digital-india/
4. https://economictimes.indiatimes.com/hindi/wealth/personal-finance/digital-india-programme-what-you-need-to-know-details-in-hindi/articleshow/80748189.cms
5. https://hindi.news18.com/news/tech/what-is-umang-app-all-you-need-to-know-nodvkj-3310555.html
6. https://www.hindinotes.org/2019/02/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-what-is-digital-india-in-hindi.html

❑❑❑